**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्‍चतर शिक्षा विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 1673

उत्‍तर देने की तारीख: 27.12.2018

**उच्चतर शिक्षण संस्थानों में पुस्तकालय की सुविधाएं**

**1673. प्रो॰ मनोज कुमार झाः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उच्चतर शिक्षण संस्थानों में पुस्तकालय की सुविधाओं के लिए वार्षिक बजट परिव्यय और व्यय, बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान और वर्तमान वर्ष के लिए बजट का विश्वविद्यालय-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पुस्तकालयाध्यक्षों की नियमित नियुक्ति नहीं की जाती है और उन्हें केवल 5 साल के अनुबंध पर रखा जाता है; और

(ग) क्या पुस्तकालयों को विश्वविद्यालयों की गौण सेवाएं समझा जाता है?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(डॉ. सत्‍य पाल सिंह)**

(क): यूजीसी विश्वविद्यालयों में आधारिक संरचना और मूलभूत सुविधाओं अर्थात् पुस्तकालय सहित भवन एवं परिसर का विकास में सुधार के लिए ब्लॉक विकास अनुदान प्रदान करता है।

केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए वर्ष 2018-19 के दौरान ‘पुस्तकों और पत्रिकाओं’ के आवंटन का विवरण <http://www.ugc.ac.in/pdfnews/2768334RSPQ-1673-FCU-Annexure-I.pdf> पर उपलब्ध है।

यूजीसी ने 12वीं योजना 2012-17, जिसे 31.03.2019 तक बढ़ा दिया गया है, के तहत सामान्य विकास सहायता (जीडीए) योजना के अंतर्गत यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 2 (च) और 12 (ख) में सूचीबद्ध पात्र राज्‍य विश्‍वविद्यालयों को वित्‍तीय सहायता भी प्रदान की है।

यूजीसी द्वारा 12वीं योजना अवधि के दौरान सामान्य विकास योजना के तहत ‘पुस्तकों और पत्रिकाओं’ सहित राज्य विश्वविद्यालयों को आवंटित और जारी की गई धनराशि का  ब्‍यौरा [http://www.ugc.ac.in/pdfnews/3211377RSPQ-1673 Annexure-II.pdf](http://www.ugc.ac.in/pdfnews/3211377RSPQ-1673%20Annexure-II.pdf) पर उपलब्ध है।

(ख) और (ग): जी, नहीं। लाइब्रेरियन को नियमित आधार पर नियुक्त किया जाता है। पुस्तकालय, डिजिटल पहुंच सहित सूचना एवं इस तरह के संसाधनों के स्रोतों का संग्रह है, जिन्‍हें शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक समुदाय दोनों के लिए सुलभ कराया जाता है और स्वतंत्र अनुसंधान को विकसित करने हेतु सहयोगी अधिगम सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है।

**\*\*\*\*\***